| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com| Impact Factor: 5.928|Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 3, Issue 10, October 2020 |

मेरठ षड्यंत्र केस- एक ऐतिहासिक अध्ययन

Dr. Abhinandan Swaroop

M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly, Uttar Pradesh, India

सार

मेरठ षड्यंत्र मामला एक विवादास्पद अदालत का मामला था। मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओ को बन्दी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुक़दमा चलाया। इनमें तीन ब्रिटिश साम्यवादी फिलिप स्प्रेड, बैन ब्रेडले तथा लेस्टर हचिंसन भी थे। इन तीनों ब्रिटिश कम्युनिस्टों को भारत से निष्कासित करने का विधेयक तैयार किया था। इन पर आरोप लगाया गया कि ये सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे।मेरठ षड्यंत्र केस के विरोध में 21 मार्च 1929 को मोतीलाल नेहरू में केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया। आइंस्टाइन ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर इस मुकदमे को हटा लेने की मांग की। मेरठ षड्यंत्र केस में फंसे कैदियों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, एम ए अंसारी, कैलाश नाथ काटजू तथा एम.जी. छागला ने पैरवी की ।मेरठ षड्यंत्र केस का फैसला 16 जनवरी 1933 ईस्वी को सुनाया गया। 27 अभियुक्तों को कड़ी सजा दी गई। मुजफ्फर अहमद को सबसे बड़ी और कड़ी सजा दी गई जिसके तहत उन्हें आजीवन काले पानी की सजा दी गई। इससे श्रमिक आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

परिचय

मेरठ षड्यंत्र मामला एक विवादास्पद अदालत का मामला था। मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओ को बन्दी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुक़दमा चलाया। इनमें तीन ब्रिटिश साम्यवादी फिलिप स्प्रेड, बैन ब्रेडले तथा लेस्टर हचिंसन भी थे। इन तीनों ब्रिटिश कम्युनिस्टों को भारत से निष्कासित करने का विधेयक तैयार किया था। इन पर आरोप लगाया गया कि ये सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे।[1]

मेरठ षड्यंत्र केस के विरोध में 21 मार्च 1929 को मोतीलाल नेहरू में केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया। आइंस्टाइन ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर इस मुकदमे को हटा लेने की मांग की। मेरठ षड्यंत्र केस में फंसे कैदियों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, एम ए अंसारी, कैलाश नाथ काटजू तथा एम.जी. छागला ने पैरवी की ।[2]

मेरठ षड्यंत्र केस का फैसला 16 जनवरी 1933 ईस्वी को सुनाया गया। 27 अभियुक्तों को कड़ी सजा दी गई। मुजफ्फर अहमद को सबसे बड़ी और कड़ी सजा दी गई जिसके तहत उन्हें आजीवन काले पानी की सजा दी गई। इससे श्रमिक आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्रो. धर्मवीर को कुछ दिन बाद ही छोड़ दिया गया था, जबकि बाकी 31 पर मेरठ में मुकदमा चलाया गया। इन्हें बचाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, एम ए अंसारी, कैलाश नाथ काटजू और एमजी छागला ने पैरवी की थी। बंगाली ट्रेड यूनियन नेताओं शिबनाथ बनर्जी, किशोरी घोष और बीएन मुखर्जी को बरी कर दिया गया था। डॉ. आर ठेंगडी की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई थी। 27 आंदोलनकारियों को दो साल से लेकर आजावीन काले पानी तक की सजा दी गई थी।[3,4]

मेरठ षडयंत्र केस एक विवादास्पद अदालती मामला था जिसे मार्च 1929 में ब्रिटिश राज में शुरू किया गया था और 1933 में फैसला किया गया था । भारतीय रेलवे हड़ताल के आयोजन के लिए तीन अंग्रेजों सहित कई ट्रेड यूनियनों को गिरफ्तार किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने एक मुकदमे के तहत 27 वामपंथी ट्रेड यूनियन नेताओं को दोषी ठहराया। परीक्षण ने तुरंत इंग्लैंड में ध्यान आकर्षित किया , जहां इसने 1932 के नाटक मेरठ को एक मैनचेस्टर स्ट्रीट थिएटर समूह, रेड मेगाफोन्स द्वारा प्रेरित किया , जिसमें इसके हानिकारक प्रभावों को उजागर किया गया था। उपनिवेशीकरण और औद्योगीकरण । [1]

ब्रिटिश सरकार कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बढ़ते प्रभाव के बारे में स्पष्ट रूप से चिंतित थी । यह भी पूरी तरह से आश्वस्त था कि कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारों की सभी घुसपैठ को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) द्वारा श्रमिकों के बीच प्रचारित किया गया था। इसका अंतिम उद्देश्य, सरकार ने माना, "सामान्य हड़ताल और सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से" पूर्ण पक्षाघात और हर देश (भारत सहित) में मौजूदा सरकारों को उखाड़ फेंकना था। [2] सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया एक और साजिश का मामला, मेरठ साजिश का मामला, को विफल करने के लिए थी।[5]

एक से अधिक तरीकों से, मुकदमे ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को श्रमिकों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की। 32 अन्य व्यक्तियों के साथ डांगे को 20 मार्च 1929 [2] को गिरफ्तार किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 121ए के तहत मुकदमा चलाया गया :

जो कोई भी ब्रिटिश भारत के भीतर या बाहर धारा 121 द्वारा दंडनीय किसी भी अपराध को करने की साजिश करता है या ब्रिटिश भारत या उसके किसी भी हिस्से की संप्रभुता से राजा को वंचित करता है, या आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com| Impact Factor: 5.928|Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 3, Issue 10, October 2020 |

माध्यम से आतंकित करने की साजिश करता है, भारत सरकार या किसी भी स्थानीय सरकार को जीवन भर के लिए परिवहन, [3] या किसी भी छोटी अवधि के लिए, या किसी भी विवरण के कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो दस साल तक बढ़ सकता है।

मुख्य आरोप यह थे कि 1921 में एसए डांगे , शौकत उस्मानी और मुजफ्फर अहमद भारत में कॉमिन्टर्न की एक शाखा स्थापित करने की साजिश में शामिल हो गए और उन्हें आरोपी फिलिप स्प्रैट और बेंजामिन फ्रांसिस ब्रैडली सहित विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मदद मिली, जिन्हें बाद में भारत भेजा गया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल द्वारा। आरोपी व्यक्तियों का उद्देश्य, उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 121-ए (1860 के अधिनियम 45) के तहत था:

ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के राजा सम्राट को वंचित करने के लिए, और इस तरह के उद्देश्यों के लिए तरीकों का उपयोग करने और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल द्वारा उल्लिखित और अभियान के कार्यक्रम और योजना को पूरा करने के लिए।[6,7]

मेरठ में सत्र न्यायालय ने जनवरी 1933 में अभियुक्तों को कड़ी सजा सुनाई। अभियुक्तों में से 27 व्यक्तियों को 'परिवहन' की विभिन्न अवधियों के साथ दोषी ठहराया गया था। मुजफ्फर अहमद को जीवन के लिए परिवहन किया गया था, और डांगे, स्प्रैट, घाटे, जोगलेकर और निंबकर को 12 साल की अवधि के लिए परिवहन से सम्मानित किया गया था। अपील पर, अगस्त 1933 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर शाह सुलेमान द्वारा अहमद, डांगे और उस्मानी की सजा को घटाकर तीन साल [4] कर दिया गया था, इस आधार पर कि आरोपी पहले ही अपनी सजा का काफी हिस्सा खर्च कर चुके थे। जबकि वे मुकदमे के फैसले का इंतजार कर रहे थे और क्योंकि

अभियुक्तों के विश्वासों से उत्पन्न होने वाले राजनीतिक अपराधों के मामले में, गंभीर दंड उनके उद्देश्य को विफल करते हैं। व्यवहार में ऐसे वाक्य अपराधियों को उनके विश्वास की पुष्टि करते हैं और अन्य अपराधियों को पैदा करते हैं, इस प्रकार बुराई और जनता के लिए खतरा बढ़ जाता है।

दोषी ठहराए गए अन्य लोगों की सजा भी कम कर दी गई। [2]

अपील पर देसाई, हचिंसन, मित्रा, झाबवाला, सहगल, कासले, गौरी शंकर, कदारा और अल्वे की दोषसिद्धि भी पलट दी गई।[8]

सभी आरोपी कम्युनिस्ट थे । [9,10] उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों ने भारत में कम्युनिस्ट विचारों के विकास के ब्रिटिश सरकार के डर को चित्रित किया । मुकदमे में, सभी अभियुक्तों को बोल्शेविकों के रूप में लेबल किया गया था । साढ़े चार साल तक, प्रतिवादियों ने अदालत कक्ष को अपने मुद्दों को उठाने के लिए एक सार्वजनिक मंच में बदल दिया। परिणामस्वरूप, परीक्षण ने देश में कम्युनिस्ट आंदोलन को मजबूत होते देखा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पूर्व महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत ने मेरठ षडयंत्र मामले के बाद के बारे में लिखा:

एक केंद्रीकृत तंत्र वाली पार्टी, 1933 में मेरठ के कैदियों की रिहाई के बाद ही अस्तित्व में आई। मेरठ षड्यंत्र केस, हालांकि कम्युनिस्ट आंदोलन को दबाने के लिए शुरू किया गया था, कम्युनिस्टों को अपने विचारों का प्रचार करने का अवसर प्रदान किया । यह अपने स्वयं के घोषणापत्र के साथ सामने आया और 1934 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से संबद्ध हो गया । [5]

विचार-विमर्श

वर्ष 1928 ने ब्रिटिश सरकार को बुरे सपने की एक श्रृंखला के साथ प्रस्तुत किया: श्रमिकों के आंदोलन में भव्य पुनरुत्थान, राष्ट्रीय राजनीति में उनकी बढ़ती भागीदारी और इन दोनों विकासों में कम्युनिस्टों की प्रमुख भूमिका; WPPs का तेजी से प्रसार और राष्ट्रीय स्तर पर उनका समेकन; साइमन कमीशन द्वारा उकसाए गए व्यापक साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का पुनरुद्धार; भगत सिंह और उनके साथियों की क्रांतिकारी गतिविधियाँ; अंतिम लेकिन कम नहीं, कम्युनिस्टों और राष्ट्रवादी नेतृत्व के एक वर्ग के करीब आना। 1929 में राज ने पलटवार किया। इसका पहला लक्ष्य स्वाभाविक रूप से WPPs के माध्यम से काम करने वाले कम्युनिस्ट थे, क्योंकि वे तेजी से राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की सबसे शक्तिशाली जन धारा बन रहे थे। इस प्रकार प्रसिद्ध मेरठ षडयंत्र केस शुरू हुआ,[10,11]

हमले की योजना उच्चतम स्तर पर बनाई गई थी। लंदन में भारत के लिए गृह सचिव को गवर्नर-जनरल इरविन का एक गुप्त टेलीग्राम बताता है, "भारतीय राजनीतिक स्थिति ने वामपंथी बदलाव की सराहना की थी और हम निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका जताते हैं।" (गुप्त दूरभाष संख्या 2555, 19 जनवरी एफ / एन संख्या 184/29, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, लंदन, गौतम चट्टोपाध्याय के पेशावर से मेरठ तक उद्धृत और अनुवादित, ओप । सीआईटी., पृ. 75.). इसलिए, 20 मार्च, 1929 को कलकत्ता, बंबई, यूपी और पंजाब के 31 श्रमिक नेताओं (नीचे दी गई सूची देखें) का व्यापक दौर हुआ। और उन्हें मेरठ षडयंत्र केस के लिए मेरठ लाया गया। तीन अंग्रेज, ब्रैडली, फिलिप स्प्रैट और लेस्टर हचिंसन, जो मजदूर वर्ग के आंदोलन में सक्रिय थे और एआईसीसी के आठ सदस्य गिरफ्तार किए गए थे। पूरे देश में व्यापक तलाशी अभियान में बड़ी संख्या में प्रकाशित और अप्रकाशित दस्तावेज, पत्र, पत्रिकाएं, पत्रक आदि जब्त किए गए और इंटरसेप्ट किए गए पत्राचार के साथ सबूत के तौर पर पेश किए गए। मेरठ को साजिश के

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com| Impact Factor: 5.928|Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 3, Issue 10, October 2020 |

मुकदमे के लिए चुना गया था क्योंकि ब्रिटिश "मामला जूरी को प्रस्तुत करने का मौका नहीं ले सकते थे।" (गृह सदस्य एचजी हैग, गोपनीय नोट, 20 फरवरी '29)।[12,13]

लेकिन इस बार ब्रिटिश उद्देश्य कम से कम एक मामले में प्रतिकूल साबित हुआ। पिछले साम्यवाद-विरोधी मुकदमे का स्थल कानपुर जहाँ भाकपा का जन्म स्थान बन गया था, वहीं मेरठ साम्यवादी प्रचार का एक शानदार मंच बन गया। आरोपी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए कोर्ट रूम का इस्तेमाल करने के लिए, उनके कार्यक्रमों, एमिस और उद्देश्यों के लिए बेहतर तरीके से संगठित थे। साम्यवादियों और राष्ट्रवादी नेताओं के बीच दरार डालने की ब्रिटिश चाल भी व्यर्थ साबित हुई। नेहरू, गांधी और कई अन्य लोगों ने मेरठ जेल का दौरा किया जबकि आरोपी कम्युनिस्टों ने सत्याग्रहियों को संदेश भी भेजेविभिन्न जेलों में राजनीतिक स्थिति के लिए उनके उचित संघर्षों का समर्थन करते हुए। आरोपी कम्युनिस्टों ने मामले को महानगरीय शहरों में से एक में स्थानांतरित करने की भी कोशिश की लेकिन इस अपील को सत्र न्यायालय ने ठुकरा दिया। इसके अलावा विदेश से गवाहों का उपयोग करने का उनका प्रयास और मामले की रक्षा के लिए नेशनल मेरठ प्रिजनर्स डिफेंस कमेटी द्वारा इंग्लैंड से एक वकील की व्यवस्था और राजनीतिक सलाहकार के रूप में सीपीजीबी के कॉमरेड जेआर कैंपबेल की मदद को ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 ए (देशद्रोह से जुड़े अपराध) के तहत साजिश का मुकदमा आरएल यॉर्क के मेरठ सत्र न्यायालय में चलाया गया था। बचाव पक्ष के दो वकील केएफ नरीमन और एमसी छागला आरोपी की ओर से पेश हुए। अपने बचाव में अलग-अलग बयान देने के अलावा, मजिस्ट्रेट और सत्र अदालत के परीक्षणों के दौरान 18 कम्युनिस्ट अभियुक्तों का एक सामान्य बयान दिया गया था। इस सामान्य बयान ने भारत में ब्रिटिश शासन के दिवालिएपन और पाखंड और उनकी 'सभ्य' कानूनी व्यवस्था को जोरदार ढंग से उजागर किया और कम्युनिस्ट कार्यक्रम और नीतियों को सामने रखा (लघु अंशों के लिए पाठ VI-25 देखें।) चार साल के दिखावटी परीक्षण के बाद, 16 जनवरी 1933 को फैसला सुनाया गया। यह इस प्रकार था:[14]

1. मुजफ्फर अहमद ——- जीवन के लिए परिवहन।
2. सदांगे ————— बारह वर्षों की अवधि के लिए परिवहन।
3. फिलिप स्प्रैट ———— वही-
4. एसवीघाटे ————- -वही-
5. केएन जोगलेकर ———— - वही
6. आर.एस.निंबकर ———— - वही
7. बेंजामिन फ्रांसिस —— दस वर्षों के लिए ब्रैडली के लिए परिवहन।
8. एसएस मिराजकर ———— -वही-
9. शौकत उस्मानी ——- -वही-
10. मीर अब्दुल मजीद —— सात वर्ष का परिवहन।
11. सोहन सिंह जोश ——————- -वही-
12. धरणीकान्त गोस्वामी —————- -वही-
13. अयोध्या प्रसाद ——————— पांच वर्ष का परिवहन।
14. जी. अधिकारी ————————- वही-
15. पीसी जोशी ————————— -वही-
16. एमजी देसाई —————————- वही-
17. गोपेन चक्रवर्ती —————- चार वर्ष का आर.आई.
18. गोपाल चंद्र बासक —————- -वही-
19. एचएल हचिंसन ——————- वही-
20. राधा रमन मित्र —————— -वही-
21. शिवावकाश होमरजी झाबवाला ———- -वही-
22. केदार नाथ सहगल ——————— वही-
23. शम्सुल हुदा ————————— तीन साल की आरआई
24. अर्जुन आत्माराम अल्वे ——————— वही-
25. गोबिंद रामचंद्र कासले ————— -वही-
26. गौरी शंकर ————————- -वही-
27. लक्ष्मण राव कदम ——————— वही-
28. डीआर ठेंगड़ी ——————————— फैसला लिखे जाने के दौरान निधन हो गया।
29. विश्वनाथ मुखर्जी ——————- गोरखपुर से बरी
30. सिबनाथ बैनर्जी ——————— वही-
31. किशोरीलाल घोष ——————— वही-

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com| Impact Factor: 5.928|Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 3, Issue 10, October 2020 |

सत्र परीक्षण समाप्त होने के बाद, आरोपी कम्युनिस्टों ने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय में, डॉ कैलास नाथ काटजू और दो कनिष्ठ अधिवक्ता श्याम कुमारी नेहरू और रंजीत सीताराम पंडित बचाव पक्ष के वकील के रूप में उपस्थित हुए। बैठने के आठ कार्य दिवसों के बाद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अपना फैसला इस प्रकार सुनाया:
ए) 1. एमजी देसाई, 2. एचएल हचिंसन, 3. एसएच झाबवाला, 4. राधा रमन मित्रा, 5. केदारनाथ सहगल, 6. गोबिंदा कासले, 7. गौरी शंकर, 8. लक्ष्मण राव कदम, 9. अर्जुन आत्माराम अल्वे — सभी बरी।
B) 1. अयोध्या प्रसाद, 2. पीसी जोशी, 3. गोपाल बसाक, 4. डॉ. जी अधिकारी, 5. शम्सुल हुदा - अदालत ने सत्र न्यायालय द्वारा आईपीसी की 121A के तहत सजा को बरकरार रखा, लेकिन सजा पहले ही मिल चुकी है , वे सभी रिहा हो गए।[15,16]
सी) i) गोपेन चक्रवर्ती सात महीने का आरआई
ii) एसवीघाटे एक वर्ष का आरआई।
iii) केएन जोगलेकर -वही-
iv) आरएस निंबकर -वही-
v) बीएफ ब्राडली -तदेव-
vi) एसएस मिराजकर -वही-
vii) एसएस जोश -तदेव-
viii) धरणीकांत गोस्वामी -वही-
ix) मीर अब्दुल मजीद -वही-
घ) i) मुजफ्फर अहमद तीन वर्ष का आरआई।
ii) एसए डांगे -तदेव-
iii) शौकत उस्मानी -वही-
ई) i) फिलिप स्प्रैट दो साल का आरआई।
"ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस और अन्य के दबाव में बाद में (उच्च न्यायालय द्वारा) सजा कम कर दी गई" कनाडा के प्रोफेसर माइकल ब्रेचर ने लिखा (नेहरू: एक राजनीतिक जीवनी, पृष्ठ 136)। न केवल दुनिया भर के श्रमिकों ने मुकदमे और दोषसिद्धि के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, यहां तक कि रोमेन रोलैंड और प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे पुरुषों ने भी मामले के विरोध में आवाज उठाई। हेरोल्ड लास्की ने लिखा:
"मेरठ परीक्षण उन मामलों की श्रेणी से संबंधित है जिनमें अमेरिका में मूनी परीक्षण और साको-वांगेटी परीक्षण, फ्रांस में ड्रेफस परीक्षण, जर्मनी में रैहस्टाग अग्नि परीक्षण, सर्वोच्च उदाहरण हैं।" [1]
मेरठ मुकदमे [2] ने साम्यवादियों को स्वतंत्रता के लिए अग्रणी सेनानियों के रूप में पेश किया, जिन्होंने साम्राज्यवादी हमले का खामियाजा भुगता। इसने उन्हें वास्तव में राष्ट्रीय समर्थन अर्जित किया - यहां तक कि गांधी जैसे पुरुषों ने भी अपनी सहानुभूति और सम्मान व्यक्त करने के लिए मजबूर महसूस किया। लेकिन भाकपा कोई फसल काटने में विफल रही; पहली बात तो यह कि व्यावहारिक रूप से सभी नेताओं की नज़रबंदी, ठीक उसी समय जब पार्टी खुद को मजबूत करने की योजना बना रही थी, किसी भी राष्ट्रीय स्तर की योजना और कार्य को असंभव बना दिया। दूसरे, जमीनी स्तर से धीरे-धीरे उभरा नया नेतृत्व नई कॉमिन्टर्न लाइन का पालन करने में राजा की तुलना में अधिक वफादार साबित हुआ, जो छठी विश्व कांग्रेस के ठीक बाद बाईं ओर अधिक स्थानांतरित हो गया। [17]

परिणाम

मेरठ षड्यंत्र केस (1929) भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह ऐसे समय में आया जब पूरी पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, जबकि सोवियत रूस का नवजात समाजवादी राज्य जबरदस्त प्रगति कर रहा था। इस अवधि के दौरान, जुझारू मजदूर वर्ग संघर्ष, जिनमें से अधिकांश कम्युनिस्टों और क्रांतिकारियों के नेतृत्व में थे, एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए।मजदूरों की हड़तालों की संख्या, जो 1921 में (खिलाफत-असहयोग आंदोलन की अवधि के दौरान) चरम पर पहुंच गई थी, असहयोग आंदोलन की वापसी के साथ घट गई। लेकिन 1920 के दशक के उत्तरार्ध से, एक बार फिर हम हड़तालों के कारण खोए हुए मानव-दिनों की संख्या में वृद्धि देखते हैं। यह 1928-29 में परिलक्षित होता है, जहां 203 हड़तालें हुईं और 3,16,47,404 श्रम दिवसों की हानि हुई।1929 के अंत से शुरू हुई महामंदी ने भारत को कई तरह से प्रभावित किया और श्रमिक वर्ग और किसानों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे वे विरोध में और भी बड़ी संख्या में बाहर आने के लिए मजबूर हो गए। यह घटना 1930 के शुरुआती वर्षों में जारी रही। मज़दूरों के संघर्षों का तेज़ होना उस राजनीतिक चेतना का प्रदर्शन था जो मज़दूर वर्ग के आन्दोलन के साथ-साथ बढ़ने लगी थी।अधिकांश मजदूर वर्ग और किसान संघर्षों का नेतृत्व कम्युनिस्टों ने मजदूरों और किसानों की पार्टियों (WPP) के बैनर तले किया था। 1928 में, बारडोली आंदोलन, सबसे सफल किसान लामबंदियों में से एक, बंबई में गिरनी कामगार हड़ताल के समय हुआ

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com| Impact Factor: 5.928|Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 3, Issue 10, October 2020 |

था। हालांकि दोनों काफी असंबद्ध थे और उनका कोई संगठनात्मक संबंध नहीं था, अंग्रेजों को दोनों के बीच संबंध होने का डर था और 'निश्चित थे कि अगर सरकार वहां कार्रवाई करती है तो कम्युनिस्ट बारडोली स्थिति का उपयोग करेंगे'। अंग्रेजों में कम्युनिस्टों का ऐसा डर था।

कम्युनिस्टों और WPP की गतिविधियों ने आम लोगों की चेतना में वृद्धि में योगदान दिया था, जो अब विश्वव्यापी साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता के संघर्ष का पता लगा सकते थे। कांग्रेस को भी इस बात को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस अवधि के दौरान डब्ल्यूपीपी के काम का एक और बड़ा प्रभाव क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर पड़ा। उनमें से कई साम्यवादी विचारों के प्रभाव में आ गए और इस वर्ग के सामान्य दृष्टिकोण में पर्याप्त परिवर्तन का पहला संकेत साम्यवादी आंदोलन का विकास था। इस तरह के परिवर्तन का एक स्पष्ट प्रमाण भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन था। उन दिनों जब आम तौर पर लोग 'बम-राजनीति' या गांधीवादी अहिंसा के संदर्भ में सोच रहे थे, WPP और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किए गए प्रचार ने 'मजदूर वर्ग की राजनीति' को सामने ला दिया। कम्युनिस्टों द्वारा प्रचारित पूर्ण स्वतंत्रता के लिए पूरी मेहनतकश जनता को एकजुट करते हुए सीधी कार्रवाई के विचार से युवा आकर्षित हुए।जनता के बीच इस तरह के साम्यवादी प्रभाव के फैलने से अंग्रेजों को ठीक-ठीक डर था और उन्होंने साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए तुरंत उपाय शुरू किए। दिसंबर, 1928 में, ब्रिटिश राज्य सचिव ने वायसराय को बताया कि सरकार 'प्रस्तावित साजिश परीक्षण' के संबंध में जानकारी एकत्र कर रही थी। वायसराय इरविन ने बंगाल के गवर्नर (जनवरी 18, 1929) को लिखा: “हमारे पास .... वर्तमान में इन पुरुषों के खिलाफ एक व्यापक साजिश का मामला चलाने में सक्षम होने की काफी अच्छी उम्मीदें हैं। यदि हम ऐसा कर पाते हैं, तो हमारी राय में, यह भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन को किसी भी चीज़ से अधिक गहरा आघात पहुँचाएगा।"[16,17]

इस प्रकार शुरू हुआ, मेरठ षडयंत्र केस 15 मार्च, 1929 को शुरू हुआ, जब मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने एक दिन पहले ही भारतीय दंड संहिता की धारा 121-ए के तहत अभियोजन शुरू करने की मंजूरी दी थी।20 मार्च, 1929 को भारत के विभिन्न हिस्सों में इकतीस कम्युनिस्ट/श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से ज्यादातर ट्रेड यूनियन और मजदूर वर्ग के आंदोलन के जाने-माने व्यक्ति थे। उनमें से तेरह बंबई से, दस बंगाल से, पांच यूपी से, तीन पंजाब से और तीन अंग्रेज थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आठ सदस्य और हाल ही में स्थापित WPP की कार्यकारी समिति के लगभग हर सदस्य शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी के साथ सघन छापेमारी और घरों की तलाशी ली गई।परीक्षण के लिए मेरठ का चयन सुनियोजित था। मुख्य रूप से, अधिकारी जूरी द्वारा परीक्षण से बचना चाहते थे। बंबई और कलकत्ता दोनों में, कम्युनिस्ट गतिविधियों के दो प्रमुख केंद्र, मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा एक जूरी के साथ की जाती। गृह विभाग के एक 'अत्यंत गुप्त' दस्तावेज ने अंग्रेजों के असली मकसद को उजागर कर दिया: "हम नहीं कर सकते थे ... मामले को जूरी को सौंपने का मौका। मामला कितना भी अच्छा क्यों न हो, इस बात का कोई आश्वासन नहीं हो सकता है कि एक जूरी दोषी ठहराएगी, और हम इस मामले को अदालत में तब तक नहीं रख सकते जब तक कि हम आश्वस्त न हों कि इसका परिणाम दोषसिद्धि होगा। इसी दस्तावेज़ में आगे कहा गया है: "मुंबई और कलकत्ता दोनों में श्रमिक आबादी के बीच प्रचलित खतरनाक माहौल के साथ, इनमें से किसी भी स्थान पर परीक्षण करना स्पष्ट रूप से अवांछनीय है"।इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले को उद्धृत करने के लिए मामले को 'विशाल पैमाने' पर आयोजित किया गया था। कार्यवाही लगभग साढ़े चार साल तक चली। मामले में साक्ष्य में फोलियो आकार के पच्चीस मुद्रित खंड शामिल थे। कुल मिलाकर, 3,500 अभियोजन प्रदर्शन, 1,500 से अधिक रक्षा प्रदर्शन और 320 से कम गवाहों की जांच नहीं की गई। निर्णय दो मुद्रित संस्करणों में था जिसमें फोलियो आकार के 676 पृष्ठ शामिल थे। मामले को उच्च न्यायालय में भेजे जाने से पहले ही सरकार ने सरकारी खजाने से सोलह लाख रुपये खर्च कर दिए।[15,16]

पिछले 'कम्युनिस्ट षड्यंत्र' के मामलों के विपरीत, मेरठ के कैदियों ने अपने एजेंडे को यथासंभव अधिक से अधिक प्रचारित करने के लिए एक मंच के रूप में अदालत का उपयोग करने का निर्णय लिया। मुजफ्फर अहमद ने अधिकारी से कहा कि उन्हें राजनीतिक बयान देकर सत्र न्यायालय को एक प्रचार मंच में बदलना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने खुद को अध्ययन के माध्यम से तैयार करने का फैसला किया। सभी अभियुक्तों की ओर से सामान्य बयान औपचारिक रूप से आरएस निंबकर द्वारा पेश किया गया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्तों की 'मुख्य उपलब्धियां' 'श्रमिकों और किसानों की पार्टियों की स्थापना' थी और "गंभीरता की बात यह थी कि बॉम्बे पार्टी के सदस्यों ने कार्यकर्ताओं पर पकड़ बना ली थी। बंबई में कपड़ा उद्योग में जैसा कि 1928 की हड़ताल के दौरान उनके नियंत्रण की सीमा और हड़ताल समाप्त होने के बाद गिरनी कामगार

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com| Impact Factor: 5.928|Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 3, Issue 10, October 2020 |

यूनियन में पूरी तरह से क्रांतिकारी नीति को आगे बढ़ाने में मिली सफलता से पता चलता है।कुल सत्ताईस अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया। वे थे: मुजफ्फर अहमद - जीवन के लिए परिवहन; बीस वर्षों की अवधि के लिए परिवहन - एसए डांगे, फिलिप स्प्रैट, एसवी घाटे, केएन जोगलेकर, आरएस निंबकर; दस साल की अवधि के लिए परिवहन - बीएफ ब्रैडली, एसएस मिराजकर, शौकत उस्मानी; सात साल की अवधि के लिए परिवहन - मीर अब्दुल मजीद, सोहन सिंह जोश, धरणीकांत गोस्वामी; पांच साल की अवधि के लिए परिवहन - अयोध्या प्रसाद, गंगाधर अधिकारी, पीसी जोशी, एमजी देसाई; चार साल का सश्रम कारावास - गोपेन चक्रवर्ती, गोपाल चंद्र बसाक, हचिंसन, राधारमण मित्रा, एसएच झाबवाला, केएन सहगल; तीन साल सश्रम कारावास - शम्सुल हुदा, अर्जुन आत्माराम अल्वे, जीआर कासले, गौरी शंकर और एलआर कदम।फैसले के बाद, सभी 27 दोषियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने अगस्त, 1933 में अपना फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने नौ के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया और अन्य के लिए सजा को कम करके कठोर कारावास कर दिया। उनके द्वारा पहले ही अर्जित की गई छूट की अवधि को ध्यान में रखा गया और उन सभी को नवंबर 1933 में रिहा कर दिया गया।पूरे मुकदमे को व्यापक प्रचार मिला और पूरी दुनिया में मजदूर वर्ग की एकजुटता पैदा हुई। भारत और विदेशों में, विशेष रूप से ब्रिटेन में संगठित आंदोलन के रूप में मजबूत एकजुटता की पहल के लिए मेरठ परीक्षण शायद अद्वितीय था। कॉमिन्टर्न ने गिरफ्तारी की निंदा की और ब्रिटिश श्रमिकों और कम्युनिस्टों ने एक दृढ़ एकजुटता आंदोलन बनाया। उन्होंने बंदियों के लिए चंदा इकट्ठा किया। कट्टरपंथी ब्रिटिश प्रेस ने भी इस मुद्दे पर प्रकाश डाला और परीक्षण के वर्षों के दौरान कैदियों के साथ सहानुभूति व्यक्त की। 1929 से 1933 के अंत तक, मेरठ के कैदियों के लिए एकजुटता आंदोलन एक उग्रवादी राजनीतिक आंदोलन बन गया, जिसने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के समर्थन में एक अनुकूल जनमत बनाने में मदद की।[15]

भगत सिंह और उनके साथी, जो खुद मुकदमे (लाहौर षडयंत्र केस) के तहत थे, ने मेरठ के कैदियों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। मद्रास प्रांत में स्वाभिमान आंदोलन के नेता पेरियार ईवी रामास्वामी ने मेरठ के कैदियों के साथ खुलकर सहानुभूति व्यक्त की। गांधी सहित कई कांग्रेस नेताओं ने अंग्रेजों की निंदा की और मेरठ के बंदियों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की।कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से कलकत्ता, बंबई और अन्य मजदूर वर्ग के गढ़ों में अपने नेताओं की नजरबंदी का विरोध करते हुए काम बंद कर दिया। AITUC ने खुले तौर पर परीक्षण की निंदा की। कई शहरों में छात्र और युवा भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।मेरठ एकजुटता आंदोलन ने मजदूर वर्ग की क्षमता को दिखाया। भारत में, मुकदमे ने कम्युनिस्टों को रणनीतियों और रणनीति के बारे में एक आम समझ बनाने और व्यापक चैनलों के माध्यम से प्रचार करने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान किया। 1933 के अंत में कम्युनिस्ट कैदियों की रिहाई के बाद, पार्टी अपनी गतिविधियों को फैलाने के लिए एक मजबूत राजनीतिक और संगठनात्मक आधार खोजने में सक्षम हुई। यह उन क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के बीच अपने समर्थन के आधार का विस्तार करने में भी सफल रहा, जो राष्ट्रीय मुक्ति के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश में थे।मेरठ षडयंत्र केस और लाहौर षड़यंत्र केस के तथ्यों और तर्कों ने, जो एक साथ चल रहे थे, देश के लाखों युवाओं को जन क्रांतिकारी संघर्षों का रास्ता चुनने में मदद की।[16]

निष्कर्ष

जबकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च, 1931 को फाँसी दी गई थी, कम से कम 31 कम्युनिस्ट नेता और मेहनतकश जनता के संगठनकर्ता कथित मेरठ षडयंत्र केस के तहत एक हास्यास्पद मुकदमे का सामना कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए कम्युनिस्ट नेताओं में तीन ब्रिटिश कम्युनिस्ट भी थे - बेंजामिन फ्रांसिस ब्रैडली, फिलिप स्प्रैट और लेस्टर हचिंसन - जो भारतीय मजदूर वर्ग को संगठित करने के एक आम मिशन में अपने भारतीय साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। मेरठ के कम्युनिस्टों ने भारत में ब्रिटिश शासन की वास्तविक प्रकृति को उजागर करने और क्रांति और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के कम्युनिस्ट लक्ष्यों का प्रचार करने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में परीक्षण का उपयोग किया। परीक्षण ने अंतर्राष्ट्रीय विरोध को आमंत्रित किया और ब्रिटिश ट्रेड यूनियनों और सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग आंदोलन के दबाव में,यह एक बड़े पैमाने पर राजनीतिक संघर्ष, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने में गांधीवादी अभ्यास की दूसरी प्रमुख अवधि भी थी। जब पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक निर्णायक संघर्ष शुरू करने के लिए कांग्रेस के अंदर दबाव बढ़ रहा था, गांधी ने 31 जनवरी, 1930 को ब्रिटिश शासकों को 11 सूत्री अल्टीमेटम दिया। दिलचस्प बात यह है कि इसमें भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की मांग भी शामिल नहीं थी। अकेले पूर्ण स्वतंत्रता। गांधी ने 11 मांगों का इस आधार पर बचाव किया कि वे आंदोलन के व्यापक प्रसार और समाज के बड़े वर्गों की अधिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करेंगी। इनमें से पांच आम लोकतांत्रिक मांगें थीं (निश्चित रूप से, गांधीवादी रंग के साथ): सेना के खर्च और सिविल सेवा वेतन में 50% कटौती, पूर्ण शराबबंदी, सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस जारी करने के लोकप्रिय नियंत्रण की अनुमति देने के लिए सीआईडी में सुधार और शस्त्र अधिनियम में बदलाव। तीन मांगों ने भारतीय बुर्जुआ वर्ग की विशिष्ट आकांक्षाओं को पूरा किया, जैसे, रुपये-स्टर्लिंग विनिमय अनुपात को कम करना, भारतीय कपड़ा उद्योग की सुरक्षा और

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com| Impact Factor: 5.928|Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 3, Issue 10, October 2020 |

भारतीयों के लिए तटीय नौवहन का आरक्षण। अन्य दो मुख्य रूप से जमींदार किसानों के हितों से संबंधित थे: भू-राजस्व में 50% की कमी और नमक पर नमक कर और सरकारी एकाधिकार को समाप्त करना। मजदूर वर्ग और भूमिहीन ग्रामीण गरीबों की कोई विशेष मांग स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थी! अन्य दो मुख्य रूप से जमींदार किसानों के हितों से संबंधित थे: भू-राजस्व में 50% की कमी और नमक पर नमक कर और सरकारी एकाधिकार को समाप्त करना। मजदूर वर्ग और भूमिहीन ग्रामीण गरीबों की कोई विशेष मांग स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थी! अन्य दो मुख्य रूप से जमींदार किसानों के हितों से संबंधित थे: भू-राजस्व में 50% की कमी और नमक पर नमक कर और सरकारी एकाधिकार को समाप्त करना। मजदूर वर्ग और भूमिहीन ग्रामीण गरीबों की कोई विशेष मांग स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थी![17]

संदर्भ

1) मेरठ 1932 प्ले, मैनचेस्टर स्ट्रीट थिएटर ग्रुप द रेड मेगाफोन्स द्वारा 3 मार्च 2008 को वेबैक मशीन वर्किंग क्लास मूवमेंट लाइब्रेरी में संग्रहित किया गया ।
2) ^यहां तक जायें:ए बी सी "मेरठ - परीक्षण"। 2 नवंबर 2014 कोमूलसे संग्रहीत। 2 नवंबर 2014 कोपुनःप्राप्त।
3) ↑ ब्रिटिश शासन के दौरान, अंडमान द्वीप समूह में दोषियों को दंडात्मक बंदोबस्त के लिए एक गंभीर प्रकार की सजा दी जा रही थी ।
4) ^ एसएच झाबवाला और अन्य में। बनाम सम्राट ने 3 अगस्त 1933 एआईआर सभी 690 या 145 इंड कैस 481 पर फैसला किया http://indiankanoon.org/doc/1416180/
5) ↑ सुरजीत, हरकिशन सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की 75वीं वर्षगांठ , द मार्क्सिस्ट , नई दिल्लीमें एक लेख
6) मेरठ 1929-1932: लेस्टर हचिंसन द्वारा "राजा के खिलाफ साजिश" के आरोप के खिलाफ मेरठ कोर्ट, भारत में अपने बचाव में दिया गया बयान। मैनचेस्टर मेरठ रक्षा समिति, 1932।
7) मेरठ: बंदियों को रिहा करो! राष्ट्रीय संयुक्त परिषद द्वारा मेरठ परीक्षण और सजा पर एक वक्तव्य । राष्ट्रीय संयुक्त परिषद, 1933 द्वारा प्रकाशित।
8) मेरठ में साजिश , लेस्टर हचिंसन द्वारा। आयर प्रकाशन, 1972, आईएसबीएन 0-405-04154-3 ।
9) मेरठ कॉन्सपिरेसी केस एंड द लेफ्ट विंग इन इंडिया , प्रमिता घोष द्वारा। पपीरस द्वारा प्रकाशित, 1978।
10) द ग्रेट अटैक: मेरठ कॉन्सपिरेसी केस , सोहन सिंह जोश द्वारा। पीपुल्स पब द्वारा प्रकाशित। हाउस, 1979।
11) मेरठ षडयंत्र केस और भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन, 1929-35 , देवेंद्र सिंह द्वारा। रिसर्च इंडिया द्वारा प्रकाशित, 1990।
12) मेरठ (भारत) द्वारा मेरठ कम्युनिस्ट षडयंत्र केस पर निर्णय । सत्र न्यायालय, आर एल योर्क, अधीर चक्रवर्ती, पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार। पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखागार , शिक्षा विभाग, सरकार द्वारा प्रकाशित । पश्चिम बंगाल, 1991।
13) मेरठ षड्यंत्र परीक्षण: पृष्ठभूमि, आरोप और वाक्य
14) मेरठ 1932 का नाटक, मैनचेस्टर स्ट्रीट थिएटर ग्रुप द रेड मेगाफोन्स द्वारा
15) मेरठ षड़यन्त्र प्रकरण - समाचार पत्रों की कतरनें 1929 (लिंक अद्यतन 12/2019)
16) मेरठ में हचिंसन की साजिश के लिए एच. लास्की की "प्रस्तावना" , पृष्ठ 8।
17) इस मामले पर विवरण के साथ बड़ी संख्या में पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हैं, जैसे: द ग्रेट अटैक बाय सोहन सिंह जोश, पीबीएच (नई दिल्ली, 1979); मेरठ कॉन्सपिरेसी केस एंड द लेफ्ट विंग इन इंडिया बाय प्रमिता घोष, पायरस (कलकत्ता, 1978)। इसलिए हम खुद को एक संक्षिप्त सामान्य टिप्पणी तक सीमित रखते हैं।